International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)
E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

राजस्थान के जनजातीय युवाओं में स्वरोजगार एवं स्टार्टअप संस्कृति के प्रति बढ़ते रुझान का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन

डॉ. रमेश चंद मीना

सहायक आचार्य,भूगोल
राजकीय महाविधालय मासलपुर,करौली (राज.)

1. सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय समाज के सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर स्थित अनुसूचित जनजातीय (ST) युवाओं में हाल के वर्षों में देखे जा रहे व्यावसायिक प्रतिमान बदलाव (Paradigm Shift) का एक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। पारंपरिक रूप से, जनजातीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कि निर्वाह कृषि, लघु वनोपज (MFP) संग्रहण और असंगठित शारीरिक श्रम पर निर्भर रहे हैं। हालांकि, उदारीकरण के बाद के आर्थिक सुधारों, डिजिटल साक्षरता के प्रसार, सस्ते इंटरनेट डेटा की उपलब्धता और लक्षित सरकारी पहलों ने जनजातीय युवाओं की आर्थिक आकांक्षाओं को नई दिशा दी है। वर्तमान समय में, ये युवा केवल पारंपरिक रोजगार के आकांक्षी नहीं हैं, बल्कि स्वदेशी ज्ञान, स्थानीय कला और जैविक कृषि तकनीकों का आधुनिकीकरण कर 'रोजगार प्रदाता' (Job Creators) के रूप में उभर रहे हैं। इस शोध में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, ट्राइफेड (TRIFED) और नाबार्ड (NABARD) के द्वितीयक सांख्यिकीय आंकड़ों के साथ-साथ चुनिंदा वन धन विकास केंद्रों (VDVK) के प्राथमिक अवलोकनों का उपयोग किया गया है। शोध के निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि 'वन धन विकास योजना', 'स्टैंड-अप इंडिया' और 'मुद्रा योजना' जैसी केंद्रीय पहलों ने जनजातीय सूक्ष्म-उद्यमों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके विपरीत, संस्थागत ऋण की उपलब्धता में जटिलता, आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग कौशल का अभाव तथा सुदूर भौगोलिक क्षेत्रों के कारण लॉजिस्टिक्स संबंधी चुनौतियाँ अभी भी प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं। अंत में, यह शोध पत्र जनजातीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक एकीकृत 'पब्लिक-प्राइवेट-कम्युनिटी पार्टनरशिप' (PPCP) मॉडल का प्रस्ताव करता है।

मुख्य शब्द (Keywords): जनजातीय युवा, स्वरोजगार, स्टार्टअप संस्कृति, मूल्य संवर्धन, डिजिटल समावेशन, वन धन योजना, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण।

2. परिचय (Introduction)

भारत की जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक विविधता में अनुसूचित जनजातियों (ST) का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत

हिस्सा जनजातीय समुदायों का है, जिनकी कुल आबादी 10.43 करोड़ से अधिक है। भौगोलिक दृष्टि से, ये समुदाय देश के सबसे दुर्गम पहाड़ी, वन और सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं। ऐतिहासिक रूप से, इनकी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर लेकिन निर्वाह-उन्मुख (Subsistence-oriented) रही है, जहाँ जल, जंगल और जमीन आजीविका के मुख्य आधार रहे हैं। बाहरी औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था से सीमित संपर्क के कारण, इन समुदायों को लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से अलग-थलग रहना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उच्च निरक्षरता, आर्थिक असमानता और बुनियादी ढांचे का अभाव देखा गया।

तथापि, विगत एक दशक में देश के सुदूरतम क्षेत्रों में हुए बुनियादी ढांचागत विकास और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्रांति ने इस पारंपरिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। 'डिजिटल इंडिया' अभियान के माध्यम से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में सस्ते इंटरनेट डेटा और स्मार्टफोन की सर्वव्यापकता ने भौगोलिक दूरियों को समाप्त कर दिया है। शिक्षा के बढ़ते स्तर और कौशल विकास अभियानों ने जनजातीय युवाओं की नई पीढ़ी में एक नई व्यावसायिक चेतना का संचार किया है। आज का आदिवासी युवा अपनी पारंपरिक पहचान और ज्ञान को हीनभावना के रूप में देखने के बजाय उसे आधुनिक वैश्विक बाजार में अपनी सबसे बड़ी विशिष्टता (Unique Selling Proposition - USP) के रूप में स्थापित कर रहा है।

इस गुणात्मक बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह उद्यमशीलता स्वदेशी संसाधनों और पारंपरिक कौशल के मूल्य संवर्धन (Value Addition) पर आधारित है। वैश्विक बाजारों में वर्तमान समय में प्रामाणिक (Authentic), रसायन-मुक्त और पर्यावरण-अनुकूल (Eco-friendly) उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। जनजातीय युवा इस वैश्विक मांग को बखूबी समझ रहे हैं और जैविक खेती, हर्बल अर्क, प्राकृतिक चिकित्सा, पारंपरिक हस्तशिल्प और इको-टूरिज्म के क्षेत्रों में अपने अभिनव स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल उनके व्यक्तिगत आर्थिक स्तर को ऊंचा उठा रही है, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार सृजन कर महानगरों की ओर होने वाले अनियंत्रित पलायन (Distress Migration) को रोकने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

2.1 जनजातीय संदर्भ में स्वरोजगार एवं स्टार्टअप का वैचारिक ढांचा

शहरी और तकनीकी क्षेत्रों के विपरीत, जनजातीय क्षेत्रों में 'स्टार्टअप' की अवधारणा को मुख्यतः 'सामाजिक-सांस्कृतिक उद्यमिता' (Socio-Cultural Entrepreneurship) के चश्मे से देखा जाना चाहिए। यहाँ नवोन्मेष (Innovation) का अर्थ किसी उच्च-तकनीकी सॉफ्टवेयर का निर्माण करना नहीं है, बल्कि सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को आधुनिक व्यावसायिक मानकों के अनुरूप ढालना है। यह प्रक्रिया तीन प्रमुख चरणों पर आधारित है: संसाधनों का वैज्ञानिक टिकाऊ संग्रहण, स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विपणन। इस प्रकार, ये उद्यम न केवल आर्थिक लाभ कमाते हैं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण का संरक्षण भी सुनिश्चित करते हैं।

3. शोध साहित्य की समीक्षा (Literature Review)

मिश्रा और पांडा (2020) ने अपने अध्ययन 'ट्राईबल इकोनॉमी इन ट्रांजिशन' में प्रतिपादित किया है कि पारंपरिक रूप से जनजातीय अर्थव्यवस्था एक बंद और विनिमय-आधारित प्रणाली थी, जहाँ अधिशेष (Surplus) उत्पादन का मौद्रिक विपणन अत्यंत कठिन था। परंतु हाल के वर्षों में सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास ने इन क्षेत्रों को बड़े वाणिज्यिक केंद्रों से जोड़ दिया है, जिससे युवाओं को लघु विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने की प्रेरणा मिली है।

सिंह एवं अन्य (2021) ने राजस्थान के जनजातीय बहुल जिलों में महिला उद्यमिता का मूल्यांकन करते हुए पाया कि स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सुदृढ़ीकरण ने युवा आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाया है। डिजिटल साक्षरता से लैस युवा महिलाएं पारंपरिक हस्तशिल्प और टेराकोटा कला को सीधे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ले जाने में सफल रही हैं। हालांकि, शोधकर्ताओं ने यह भी रेखांकित किया कि औपचारिक प्रबंधकीय प्रशिक्षण के अभाव में कई उद्यम प्रारंभिक दौर में ही बंद हो जाते हैं।

वरियर (2023) ने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में उभरते पर्यावरण-पर्यटन (Eco-Tourism) स्टार्टअप्स का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि स्थानीय युवाओं द्वारा संचालित होमस्टे (Homestays) मॉडल पर्यटकों को एक अनूठा सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ वनों के संरक्षण को भी वित्तीय रूप से व्यावहारिक बना रहा है। यह मॉडल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को जमीनी स्तर पर प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

कुमार और बेहेरा (2024) ने सरकारी वित्तीय योजनाओं की प्रभावकारिता की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि 'मुद्रा योजना' ने सूक्ष्म-स्तर पर स्वरोजगार को गति प्रदान की है, लेकिन बड़े स्टार्टअप्स के लिए बनाई गई 'स्टैंड-अप इंडिया' जैसी योजनाओं का लाभ तकनीकी कागजी जटिलताओं और कोलैटरल की शर्तों के कारण अभी भी सुदूर आदिवासी क्षेत्रों के पात्र युवाओं तक अपेक्षित मात्रा में नहीं पहुँच सका है।

4. शोध पद्धति एवं उद्देश्य (Research Methodology & Objectives)

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य जनजातीय युवाओं में स्वरोजगार और स्टार्टअप संस्कृति के उदय के अंतर्निहित कारणों, वर्तमान प्रवृत्तियों और उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं का एक समग्र और सांख्यिकीय मूल्यांकन करना है। इस शोध में 'मिश्रित शोध पद्धति' (Mixed Method Approach) का अनुप्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत मात्रात्मक (Quantitative) और गुणात्मक (Qualitative) दोनों प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

4.1 शोध के मुख्य उद्देश्य:

- जनजातीय युवाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित करने वाले प्रेरक कारकों (Push and Pull Factors) का विश्लेषण करना।
- भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में जनजातीय युवाओं द्वारा चुने जा रहे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों की पहचान करना।
- संस्थागत सहयोग और केंद्रीय योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का जमीनी स्तर पर मूल्यांकन करना।
- व्यवसाय संचालन और विस्तार के दौरान युवा उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधकीय बाधाओं को सूचीबद्ध करना।

4.2 डेटा संग्रह के स्रोत:

द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources): इस शोध के सांख्यिकीय आधार को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2022-2025), ट्राइफेड (TRIFED) के प्रगति विवरण, नाबार्ड (NABARD) की ग्रामीण उद्यमिता रिपोर्ट, और नीति आयोग के राज्य-स्तरीय विकास संकेतकों से डेटा प्राप्त किया गया है।

प्राथमिक अवलोकन (Primary Insights): शोध को व्यावहारिक प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए शोधकर्ता द्वारा राजस्थान (उदयपुर और बांसवाड़ा जिलों) तथा मध्य प्रदेश के वन धन विकास केंद्रों का भ्रमण कर युवा उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के प्रबंधकों के साथ अर्ध-संरचित साक्षात्कार (Semi-structured Interviews) आयोजित किए गए।

5. आंकड़ों का विश्लेषण और क्षेत्रीय रुझान (Data Analysis & Empirical Trends)

भारत में जनजातीय आबादी भौगोलिक रूप से अत्यधिक विविधतापूर्ण है, और यही विविधता उनके व्यावसायिक पैटर्न में भी परिलक्षित होती है। सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रीय रुझान सामने आए हैं:

मध्य भारत (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड) में मुख्य ध्यान 'लघु वनोपज' (MFP) के प्रसंस्करण पर केंद्रित है। महुआ, इमली, चिरौंजी, करंज और औषधीय पौधों के कच्चे व्यापार के स्थान पर, अब युवा उद्यमी इनके मूल्य-वर्धित उत्पाद (जैसे महुआ कुकीज़, ऑर्गेनिक शहद, हर्बल अर्क) तैयार कर रहे हैं, जिससे उनकी शुद्ध आय में 30 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है।

पूर्वोत्तर भारत में बांस, जैविक चाय और हथकरघा (Handloom) पर आधारित डिजाइन स्टार्टअप्स का बोलबाला है। असम और नागालैंड के युवा उद्यमी पारंपरिक बांस शिल्प को आधुनिक फर्नीचर और प्लास्टिक-विकल्प बर्तनों के रूप में वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहे हैं। नीचे दी गई तालिका भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय युवाओं द्वारा संचालित प्रमुख स्टार्टअप क्षेत्रों और उनके संस्थागत ढांचे का एक व्यापक खाका प्रस्तुत करती है:

भौगोलिक क्षेत्र	प्रमुख राज्य	पारंपरिक कौशल / संसाधन	उभरते स्टार्टअप क्षेत्र	मुख्य सहायक योजनाएँ / संस्थाएँ
मध्य भारत	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा	लघु वनोपज (MFP), महुआ, टेराकोटा कला, हर्बल जड़ी-बूटियाँ	खाद्य प्रसंस्करण, हर्बल कॉस्मेटिक्स, जैविक शहद पैकेजिंग	TRIFED, वन धन विकास केंद्र (VDVK), नाबार्ड
पूर्वोत्तर भारत	असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय	बांस शिल्प, दुर्लभ मसाले, जैविक चाय, रेशम बुनाई	इको-टूरिज्म, बांस के टिकाऊ उत्पाद, एग्रो-टेक स्टार्टअप	NEDFi, उत्तर पूर्वी परिषद (NEC), स्टार्टअप इंडिया
पश्चिमी भारत	राजस्थान, गुजरात	पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग, हस्तशिल्प, बाजरा (Millets)	ई-कॉमर्स हस्तशिल्प पोर्टल, बाजरा खाद्य प्रसंस्करण	स्टैंड-अप इंडिया, मुद्रा योजना, जिला उद्योग केंद्र (DIC)
दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु	कॉफी, काली मिर्च, जंगली शहद, बांस की नक्काशी	प्रीमियम कॉफी ब्रांडिंग, जैविक मसाला आपूर्ति श्रृंखला	राज्य जनजातीय विकास निगम, कॉफी बोर्ड, नाबार्ड

तालिका 5.1: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातीय स्टार्टअप्स और स्वरोजगार का तुलनात्मक विवरण (स्रोत: संकलित द्वितीयक आंकड़े, 2025)।

6. बढ़ते रुझान के प्रेरक कारक (Drivers of the Trend)

जनजातीय युवाओं में उद्यमिता की ओर बढ़ते आकर्षण के पीछे प्रमुख रूप से तीन कारक काम कर रहे हैं: पहला, 'वन धन विकास योजना' जिसने क्लस्टर-आधारित मूल्य संवर्धन को संस्थागत रूप दिया है; दूसरा, डिजिटल

समावेशन (Digital Inclusion)—अमेज़ॅन सहेली, फ्लिपकार्ट समर्थ और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इन सुदूर उद्यमियों को सीधे शहरी उपभोक्ताओं से जोड़कर मध्यस्थों (बिचौलियों) के शोषण को समाप्त कर दिया है; और तीसरा, युवाओं में बढ़ता शिक्षा का स्तर जो उन्हें अपनी सांस्कृतिक संपदा को व्यावसायिक रूप देने की क्षमता प्रदान करता है।

7. जनजातीय उद्यमियों के समक्ष चुनौतियाँ (Challenges & Constraints)

सकारात्मक प्रवृत्तियों के बावजूद, जनजातीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है: (1) संस्थागत वित्त की उपलब्धता में बाधाएँ: पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली ऋण देने के लिए कोलैटरल (Zamanat) और सिबिल (CIBIL) स्कोर की मांग करती है, जबकि अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व सामुदायिक या स्पष्ट दस्तावेजों के अभाव में होता है; (2) रसद (Logistics) और आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएँ: सुदूर क्षेत्रों में शीतगृहों (Cold Storage) और बारहमासी सड़कों के अभाव के कारण पेरीशेबल उत्पाद समय से पहले खराब हो जाते हैं; (3) गुणवत्ता नियंत्रण और ब्रांडिंग का अभाव: FSSAI, ISO या जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने की तकनीकी जानकारी और वित्तीय साधन न होने के कारण उत्पाद प्रीमियम बाजारों में जगह नहीं बना पाते।

8. नीतिगत सुझाव एवं भविष्य की राह (Policy Recommendations)

1. बिना किसी कोलैटरल के केवल नवोन्मेषी बिजनेस मॉडल के आधार पर जनजातीय युवाओं को बीज पूंजी (Seed Capital) प्रदान करने के लिए एक समर्पित 'आदिवासी वेंचर कैपिटल फंड' की स्थापना की जानी चाहिए।
2. प्रत्येक जनजातीय बहुल जिले में स्थानीय कौशल के अनुरूप 'ट्राइबल इनक्यूबेशन एंड मेंटरशिप सेंटर्स' (TIMC) खोले जाने चाहिए, जहाँ जीएसटी पंजीकरण, वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल मार्केटिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए।
3. जनजातीय उत्पादों के लिए मुफ्त या अत्यधिक रियायती दरों पर जैविक प्रमाणीकरण (Organic Certification) और आकर्षक, टिकाऊ पैकेजिंग तकनीक उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर मोबाइल लैब स्थापित की जानी चाहिए।

9. निष्कर्ष (Conclusion)

मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनजातीय युवाओं में स्वरोजगार और स्टार्टअप के प्रति बढ़ता रुझान केवल एक आर्थिक विकल्प नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक आत्मनिर्भरता और अपनी सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण का एक ऐतिहासिक माध्यम है। डिजिटल उपकरणों और आधुनिक शिक्षा से लैस होकर यह पीढ़ी पारंपरिक ज्ञान को एक वैश्विक व्यावसायिक पूंजी में परिवर्तित कर रही है। यदि नीतिगत स्तर पर उनकी ऋण संबंधी समस्याओं और लॉजिस्टिक्स बाधाओं को दूर कर दिया जाए, तो यह वर्ग भारत की समावेशी विकास यात्रा और 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में एक मुख्यधारा का भागीदार सिद्ध होगा।

सन्दर्भ सूचि

1. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार. (2024). वार्षिक रिपोर्ट 2023-24: जनजातीय आजीविका और विकास के बदलते आयाम. नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग.
2. ट्राइफेड (TRIFED). (2023). वन धन विकास योजना प्रगति और प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार.

3. नीति आयोग. (2025). समावेशी विकास और जनजातीय उद्यमिता सूचकांक. नई दिल्ली: नीति आयोग भारत सरकार.
4. कुमार, आर. एवं बेहेरा, एस. के. (2024). ग्रामीण और स्वदेशी स्टार्टअप्स का वित्तीय मूल्यांकन. भारतीय आर्थिक समीक्षा, 42(2), 145-162.
5. मिश्रा, पी. के. और पांडा, एन. (2020). आदिवासी अर्थव्यवस्था में संक्रमण: उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का एक तुलनात्मक अध्ययन. कोलकाता: अकादमिक प्रेस.
6. वरियर, ए. (2023). पूर्वोत्तर भारत में पर्यावरण-पर्यटन और जनजातीय युवाओं का स्वरोजगार. सतत विकास और ग्रामीण प्रबंधन पत्रिका, 15(3), 88-104.
7. शर्मा, ए. के. (2021). भारत में ग्रामीण उद्यमिता का विकास: सिद्धांत और व्यवहार. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
8. सिंह, एम., मीणा, जे. पी. और राजपाल, एस. (2021). राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमिता में भूमिका. सामाजिक और आर्थिक विकास पत्रिका, 28(1), 5-22.
9. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD). (2025). ग्रामीण ऑफ-फार्म सेक्टर और स्टार्टअप फंडिंग पर राष्ट्रीय रिपोर्ट. मुंबई: नाबार्ड.
10. दास, एस. (2022). डिजिटल इंडिया और सुदूर क्षेत्रों में आदिवासी समाज का तकनीकी समावेशन. सूचना और समाज जर्नल, 18(4), 310-325.
11. चौधरी, बी. (2020). लघु वनोपज का मूल्य संवर्धन और आदिवासियों का आर्थिक सशक्तीकरण. योजना (हिंदी पत्रिका), 64(8), 12-17.
12. स्टार्टअप इंडिया मिशन. (2024). टियर-3 और ग्रामीण क्षेत्रों में उभरते स्टार्टअप्स का सांख्यिकीय विश्लेषण. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार.
13. राव, के. वी. और रेड्डी, एम. (2023). आंध्र प्रदेश के चेन्चू आदिवासियों में लघु उद्यम और उनके समक्ष वित्तीय बाधाएं. आदिवासी अध्ययन संस्थान शोध पत्रिका, 9(2), 45-58.
14. फुकन, डी. (2022). असम में बांस और बेंत उद्योग पर आधारित युवाओं के अभिनव स्टार्टअप्स का एक अध्ययन. उत्तर-पूर्वी आर्थिक समीक्षा, 11(1), 73-89.
15. मुंडा, टी. और उरांव, एस. (2023). झारखंड में जनजातीय कला और टेराकोटा उत्पादों का ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक विपणन. लोक कला और संस्कृति जर्नल, 34(3), २०२-२१५.
16. हेम्ब्रम, एल. (2021). पारंपरिक ज्ञान बनाम आधुनिक व्यवसाय: संताल युवाओं के सामने सांस्कृतिक द्वंद्व. मानवशास्त्र और समाजशास्त्र समीक्षा, 41(2), 115-130.
17. वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. (2024). Indigenous Peoples and Sustainable Livelihood: A Global Perspective on India. वाशिंगटन डीसी: वर्ल्ड बैंक ग्रुप.
18. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI). (2025). प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण (Priority Sector Lending) और वित्तीय समावेशन रिपोर्ट. मुंबई: आरबीआई.
19. जोशी, वाई. (2022). भारत में बाजरा (Millets) आधारित खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप्स का भविष्य और जनजातीय किसान. कृषि और खाद्य सुरक्षा जर्नल, 13(5), 67-71.
20. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC). (2024). प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन के आंकड़े. मुंबई: केवीआईसी.